International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-5 Issue -10+11 Month – January+February 2018 pp. (01 – 03)

मानव संसाधन के आर्थिक अभिलक्षण भोपाल होशंगाबाद संभाग के संदर्भ में

अफरोज़ जहां

सार संक्षेप

मानव संसाधन के विकास के लिए जनसंख्या के आर्थिक अभिलक्षणों का भी उतना ही महत्व है जितना कि उसके सामाजिक अभिलक्षणों का होता है, क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में मानव समाज में सुख वैभव की अनुकूलतम दशायें लाने के लिए आर्थिक क्रियाओं का सुचारू रूप से पोषण होना अनिवार्य है। इसी अवधारणा के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन क्षेत्र के मानव संसाधन के आर्थिक अभिलक्षणों का विश्लेषणात्मक अभिज्ञान किया गया है, ताकि क्षेत्र के मानव संसाधन विकास के लिए नियोजन प्रक्रम को सार्थक बनाया जा सके। इस संदर्भ में भोपाल–होशंगाबाद संभाग की जनसंख्या में व्यवसायिक संरचना, रोजगार, बालश्रम तथा पराश्रितानुपात की विभिन्न दशाओं का आंकलन करने का प्रयास किया गया है।

परिचय :–

व्यवसायिक संरचना किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उस क्षेत्र के व्यक्तित्व एवं जीवंत स्वरूप की आर्थिक गतिशीलता पर प्रकाश डालने वाला प्रमुख सूचकांक होता है। किसी भी क्षेत्र के लोगों की व्यवसायिक संरचना उसके आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रतिबिम्ब होती है। इस तथ्य को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि समाज में श्रम विभाजन और आर्थिक विकास के स्तर तथा संसाधनों की विविधता में सुस्पष्ट सम्बन्ध है। व्यक्ति का संसाधन के रूप में महत्व किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक जनसंख्या की संरचना के आधार पर समझा जा सकता है। जिस क्षेत्र में कार्मिक जनसंख्या अधिक होती है वह क्षेत्र विकास के उच्च स्तर का द्योतक है।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 35 था जबकि भारत में 1991 में 34.1 और मध्यप्रदेश में 36.1 था। इस तरह यह प्रतिशत अध्ययन क्षेत्र में भारत की तुलना में कुछ अधिक और मध्यप्रदेश की तुलना में कुछ कम रहा है।

पद्यतिशास्त्र :–

मानव संसाधन के सामाजिक एवं आर्थिक अभिलक्षणों सम्बंधी विभिन्न निर्धारक तथ्यों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए स्तरीकृत न्यादर्श (स्ट्रेटीफाइड रेंडम सेम्पलिंग) विधि का प्रयोग कर तुलनात्मक अध्ययन।

उद्देश्य :–

1 मानव संसाधन विकास के सैद्धांतिक पक्ष की सम्यक व्याख्या करना।

2 अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध मानवीय संसाधन की पहचान एवं उनके स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण को निश्चित करना।

3 मानव संसाधन के आर्थिक अभिलक्षणों की तुलना करना।

इतिवृत्तामक संदर्भ :–

मानव संसाधन के आर्थिक विकास के संदर्भ में जो भी शोध कार्य अब तक सम्पादित हुए हैं, उनके अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इस समस्या पर किये गये कार्य बीसवीं शताब्दी की ही देन है। मानव संसाधन विकास से संबंधित जितने भी प्रमुख कार्य उल्लेखनीय हैं उनका ऐतिहासिक कालक्रम में संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

मानव संसाधन के आर्थिक विकास से संबधित उपलब्ध साहित्य के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि संसाधन की संकल्पना पर वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक के बाद ही ध्यान दिय गया है पिगोन (1920) ने संसाधन की संकल्पना आर्थिक दशा के कल्याण के लिए वर्णित की है जबकि बनार्ड (1929) मानव मस्तिष्क के प्रयोग का महत्व स्पष्ट करते है कि युक्ति पूर्ण संसाधन उपयोग के लिए मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। जिम्मरमैन (1944) ने संसाधन की व्याख्या करते हुए उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी संसाधन सम्पदा का व्याख्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है।

जिम्मरमैन (1951) ने विश्व के संसाधन एवं उद्योगों के संबंध में एक शास्त्रीय व्याख्या की है तथा साथ ही आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक मानवीय एवं सांस्कृतिक संसाधनों का वर्गीकृत रूप में उल्लेख किया है। इसी के साथ – साथ उन्होंने मानव, उसकी योग्यतायें, मानव निर्मित संस्कृति और मानव की स्वतंत्रता से संबंधित तथ्यों पर विशेष बल दिया है। उनका विश्वास है कि प्रकृति सीमायें निर्धारित करती है और मनुष्य उन सीमाओं के अन्दर अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिये अपनी कला का विकास करता है। इस प्रकार मनुष्य को द्वितीयक फलकर्ता के रूप में मान्यता दी गई क्योंकि वह अपने क्रियाकलापों में प्रकृति द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम का अनुसरण करता है।

मानव संसाधन के आर्थिक विकास से संबंधित 1960 – 70 की अवधि में बहुत ही कम ऐसे कार्य सम्पादित किये गये हैं जिनको अति महत्वपूर्ण माना जा सके। कीबिल महोदय

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-5 Issue -10+11 Month – January+February 2018 pp. (01 – 03)

(1966) का एकमात्र कार्य ऐसा है जो मानव संसाधन उपयोग से संबंधित आर्थिक विकास के तथ्यों की समीक्षा करता है।

1990 के दशक में एवं उसके पश्चात् की अवधि में मानव संसाधन विकास की संकल्पना ने विश्व क्षितिज की नई ऊँचाईयों को छू लिया है जिसकी और अनेक शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। कुमार (1992) ने मानव संसाधन के आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए उसके उपागमों का विश्लेषण किया है। कोर (1996) ने ग्रामीण विकास के लिए मानव संसाधन को नितांत आवश्यक बताया है। 19 के दशक में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में मानव संसाधन का महत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है इस हेतु भारतीय शासन शासन ने अनेक शिक्षण कार्यक्रम एवं अनेक तकनिकी का विकास किया है। तिवारी (2003) ने नये परिवेश में मानव संसाधन का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। वही राव (2003) ने मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा एवं रोजगार को महत्वपूर्ण बताया है। इसी प्रकार मानव संसाधन के पक्ष में विभिन्न शोधकर्ताओं ने अपनी शोध टिप्पणी की है इनमे सिंह (2004) एवं नीलू सिंह (2008) शुक्ल जे.आर. , गौतम (2008) ने मानव संसाधन विकास पर कार्य किया तथा सुधार वी (2008) ने संसाधन उपयोग एवं संरक्षण के संबंध में प्रकाश डाला है। यादव एच.एल. (2008) ने मानव संसाधन के आर्थिक विकास को शिक्षा के विकास से संबंधित बताया है।

मानव संसाधन की आर्थिक समस्याऐं :–

भोपाल होशंगाबाद क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए मानव संसाधन कि प्रमुख आर्थिक समस्याऐं निम्नलिखित है।

1. अध्ययन क्षेत्र में काम न करने वालों का प्रतिशत 1991 के तुलना में 2001 में अधिक हुआ है।
2. नगरीयकरण और औद्योगीकरण के कारण जो उद्यम के अवसर बढ़े है उनमें मुख्य कार्य करने वाले व्यक्ति अधिकांशतः बाहर से आने वाले कर्मी है विशेषकर भोपाल संभाग के नगरीय क्षेत्र में ।
3. अधिकांशतः दोनों संभागों के सभी जिलों में आधे से अधिक जनसंख्या का प्रतिशत काम न करने वाले व्यक्तियों का है। 1991 में यह होशंगाबाद संभाग में 64 प्रतिशत था किन्तु 2001 में सर्वाधिक भोपाल का रहा है।
4. अध्ययन के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः वयस्क व्यक्ति अब भी प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है जहा एक व्यक्ति कमानें वाला और अन्य उन पर आश्रित होते है।
5. रोजगार युक्त स्त्रियों का न्यूनतम प्रतिशत भोपाल जिले में हैं यहॉ मुस्लिम जाति की अधिकांश स्त्रियां श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करती एवं उच्च वर्ग के हिन्दू जो रूढ़िवादी विचारों से ग्रस्त है उन घरों में स्त्रियों का कार्य करना वर्जित है।
6. बालश्रम की समस्या के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव होते है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालश्रमिकों के रोजगार से प्रायः सबसे अधिक उत्पादकता वाले प्रौढ़ व्यक्यिों का रोजगार रूक जाता है। भारतीय संसद नें बालश्रम या मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये समय – समय पर कानून और अधिनियम पारित कियें है। अनुच्छेंद 21 से 24 में 6 से 14 तक के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा और आधारिक संरचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बालश्रम 1986, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों का खदानों में काम करने का निषेध करता है। यद्यपि ये अधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगों और कारखानों में बच्चों के काम करने का निषेध करता है किन्तु खतरनाक कार्यों की व्याख्या नहीं करता।
7. अध्ययन क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में वाणिज्य, वैज्ञानिक, तकनीकि व अन्य सभी शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध है। अध्ययन क्षेत्र में ये सुविधायें उपलब्ध होने के कारण युवक – युवतियां शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं किन्तु रोजगार स्तर निम्न होने के कारण बेरोजगारो के रूप में पराश्रित रहते है। इस क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है।
8. कृषि कार्य में मजदूरों की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं की खेती में बाल मजदूरी अधिक देखी गई है जिसके कारण बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते है।

समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव :–

किसी भी राष्ट्र के लियें वहां की जनसंख्या जब विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह एक निश्चित दिशा धारण कर लेती हैं और वह एक कार्यशील शक्ति बन जाती है। जब कार्यशील मानव शक्ति को एक सृजनात्मक अनुशासन प्रदान किया जाता है तो वही कार्यशील जनशक्ति मानव संसाधन बन जाती है और आर्थिक विकास में अपना योग्यदान देती है। इस संदर्भ में मानव पूंजी व्यवस्था प्रक्रम का वह स्वरूप जिसके द्वारा कार्यशील जनशक्ति में योग्यता, चातुर्य, अवसर प्राप्ति हेतु संकल्पशक्ति, कार्य संबंधी अभिप्रेरणा एवं अनुशासन की वृद्धि करने का नियोजित प्रयास किया जाता है ताकि आर्थिक उपलब्धियों को साकार बनाया जा सके। ऐसे कई उपाय है जिनके द्वारा समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

1. किसी भी क्षेत्र की जनशक्ति की सार्थकता वहां के उपलब्ध मानव संसाधन का उचिततम प्रयोग नियोजकों के लिए एक बहुत ही तार्किक एवं व्यवहारिक प्रसंग है जिसके द्वारा अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते है। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि में तीव्रता करके जनसंख्या के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि की जा सकती है।
2. रोजगारपरक शिक्षा देकर हमारे देश में बढ़ रही शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ को कम किया जा सकता है।
3. रूढ़िवादी समाज जहां स्त्रियों को कार्य करने से मना किया जाता है उनकी सोच को बदलकर आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु–कुटीर औद्योगों का विकास करके तेजी से हो रहे नगरीयकरण को रोकना जिससे नगरीय क्षेत्र के लोगों को भी आसानी से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
5. कहा जाता है कि गरीबी और जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध होता है। अतः परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करके ग्रामीण और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्ती में रहने

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-5 Issue -10+11 Month – January+February 2018 pp. (01 – 03)

वाले निर्धन लोगों के परिवार को सीमित करने और छोटे परिवार के महत्व के बारे में समझाइश देकर भी इस समस्या ने निपटा जा सकता है।

6. कार्य की गुणवत्ता में सुधार करके एवं मजूदरी करने वाले लोगों को भी सरकार की और से विशेष प्रशिक्षण देकर भी इस समस्या को कम किया जा सकत है।

7. महिलाओं को घर पर ही सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाना या अन्य कोई छोटा उघोग स्थापित करने के लिये सस्ता एवं आसानी से मिलने वाला लोन उपलब्ध होने की सुविधा कराई जानी चाहिए।

8. बालश्रमिकों के रोजगार की प्रथा उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाती है अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी के विकास के साथ ही हमारे देश का आर्थिक विकास जुड़ा है।

निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र में मानव संसाधन के आर्थिक अभिलक्षण में जनसंख्या के केवल परिणात्मक पक्ष को ही विश्लेषित नहीं किया गया है। बल्कि उसके गुणात्मक स्वरूप का भी आकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या में मुख्य कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 1991 में 35 था। जो कि 2001 में घटकर 29.25 ही रह गया है। इनमें कृषकों का प्रतिशत 1991 में 66.99 था। जो 2001 में घटकर 46.81 प्रतिशत रह गया है। इससे यह तात्पर्य होता है, कि तेजी से लोगों का रूझान कृषि की ओर कम हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में कुल अवयस्क बालकों में लगभग 22.61 प्रतिशत श्रमगत बालक है। वर्ष 1991 के आंकड़ों के अनुसार प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे 1582 व्यक्ति आश्रित थे। जिसका अनुपात 2001 में बढ़कर 2068 हो गया है। अर्थात् आश्रिततानुपात में वृद्धि हुई है।

अध्ययन क्षेत्र में यदि हम आर्थिक विकास के लक्षणों को देखते हैं तो यह अब भी पिछड़ी अवस्था में है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी अवस्था के लक्षण परिलक्षित होते है। इन क्षेत्रों में अब भी बाल श्रामिकों से कार्य लिया जाता है। एक परिवार में आश्रित व्यक्तियों की संख्या भी अधिक है। इस क्षेत्र के लोगों को पूरे वर्ष कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। एवं कृषि में आदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है।

संदर्भ सूची :–

1. एच.पी. सिंह (1989) : रिसोर्सेस एप्रेसल एण्ड प्लानिंग इन इंडिया, नई दिल्ली पेज नं. – 67 ।

2. भारत की जनगणना (1991,2001) : मध्यप्रदेश जनगणना पुस्तिका प्राथमिक जनगणना सार, मध्यप्रदेश, सीरिज – 23, पेज नं. – 121,125,128 ।

3. बी. मिश्रा एवं अटल (1987) : जनसंख्या शिक्षा सिद्धांत एवं तत्व, जनशक्ति केन्द्र, उत्तरप्रदेश पेज नं.– 216।

4. डा० पी. कुमार (1991) : मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पेज नं. – 139 – 154 ।

5. के.एम.एल. अग्रवाल (1987) : भौतिक भूगोल, साहित्य भवन, आगरा।

6. डी.एस. अवस्थी, (1985) : आर्थिक विश्लेषण, साहित्य रत्नालय, कानपुर।

7. ए.अजीज (1993) : ''फर्टिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन एण्ड इकोनोमिक स्टेटस इन मुस्लीम वोमेन'' द जियोग्राफर, वोल, VOL. XL, NO. 1

8. अहुजा श्रीराम (2000) : भारतीय समाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

9. पी.जे. भट्टाचार्य, जी.एन. शास्त्री (1976) : भारत की जनसंख्या, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

Corresponding Author : email :